वे जानते हैं कि कलकत्ते की यातायात की स्थिति बड़ी भयावह है । उन्होंने कहा कि सर्कुलर रेलवे के बारे में स्टडी चल रही है लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक सर्कुलर रेलवे बनकर तैयार होगी तब तक वहां के यातायात की समस्या और भी गहन हो जायेगी । कलकत्ते की यातायात की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि वहां अन्डरग्राउंड रेलवे या मोनो रेल नहीं बनाई जाती । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस समस्या के अध्ययन में कलकत्ते में अन्डर ग्राउंड या मोनो रेलवे बनाने की भी कोई बात है या नहीं है ?

SHRI RAGHU RAMAIAH : As I have said, the location, the feasibility and the method are being studied. The hon. Member will be glad to know that out of Rs 50 crores provision made for this purpose, for Calcutta alone, the amount comes to Rs. 34 40 crores. This itself will show that the Central Government are fully aware of the problems of Calcutta.

SHRI M. L. SONDHI : Why is Delhi being ignored ? Why is there a stepmotherly treament towards Delhi ?

SHRI TENNETI VISWANATHAM : The hon. Minister was pleased to tell us something about four cities where the traffic problem has already become very acute. But is he thinking of any preventive action so that the problem may not assume a serious proportion in other growing cities ? In a place like Visakhapatnam for example, the industrial area is sharply divided from the city area by the entrance channel to the harbour, and already a great proble has arisen there. Will the hon. Minister also include in the studies some preventive action or some action which is anticipatory of the future necessities in city like Visakhapatnam?

SHRI RAGHU RAMAIAH : Traffic study always implies study of the future type of traffic, and, therefore, any study made will naturally take the future type of traffic into account.

So far as Visakhapatnam is concerned, what I had told another hon. Member earlier will apply in this case also. This is not the end of the story. This is only the beginning. Once the patterns are studied in these four cities, other cities will be taken up according to the priorities.

SHRI TENNETI VISWANATHNAM : First priority should be given to Visakhapatnam.

ताशकंद घोषणा का निराकरण

+

*513. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 30 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1-74 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान के साथ हुए ताशकंद घोषणा का निराकरण करेगी क्योंकि पाकिस्तान इसके उपबन्धों का पालन नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार पाकिस्तान से "अनाक्रमण सन्धि" के प्रस्ताव को वापस ले लेगी क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) to (c). Government of India continue to believe that the Tashkent Declaration offers a sound framework for resolving differences with Pakistan through bilateral negotiations.

The Government also belive that a 'No-War Pact' between India and Pakistan would significantly reduce tension in the sub-continent and lead to improvement of relations between our two conntries based on mutual trust. It is our hope that Pakistan will accept this view.

श्री कंवर लाल गुप्त : जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया की आशा का सवाल है और उनके विचार जो हैं वह तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जो पाकिस्तान का रवैया उस पर है, स्वयं मन्त्री

महोदय ने बयान दिया है 16 नवम्बर को जिस में उन्होंने यह कहा है कि ताशकंद ऐग्रीमेंट में 9 क्लाज हैं। 9 में से केवल एक बात कि सेनाएं वापस कर ली जायं, उसके अलावा एक बात पर भी पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसी तरह से टेंसन है, उसी तरह से वह भारत के खिलाफ प्रचार कर रहा है। तो जब यह स्थिति है तो यह एक हमारी वीकनेस का साइन समझा जा रहा है और यह समझा जा रहा है कि हम पाकिस्तान को अपीज कर रहे हैं क्योंकि चार पांच साल से इस तरह से चल रहा है, एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं। तो क्या सरकार रूस के जरिए से ही जब यह ताशकंद ऐग्रीमेंट हुआ था तो रूस से ही कहेंगे क्योंकि यह पैकेज डील है, यह नहीं हो सकता कि एक बात पर कार्यवाही हो जाय बाकी पर न हो, तो क्या वह रूस को कहेंगे कि चूंकि पाकिस्तान ताशकंद डिक्लेरेशन पर अमल नहीं कर रहा है तो हमारे ऊपर भी यह पाबन्दी नहीं होगी कि हम उस पर अमल करें ? अगर नहीं तो उसका क्या कारण है ?

वैदेशिक कार्य-मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : जहांतक कि ताशकंद घोषणा का सवाल है उसकी बुनियाद इस पर थी कि पाकिस्तान और भारत के बीच के जो मामले हैं वह दोनों देश आपस में शांतिपूर्वक ढंग से तय करेंगे। यह उसकी शुरुआत में आया है और मैं समझता हूं कि यह बात पाकिस्तान माने या न माने इस को वापस लेने का सवाल नहीं होता। जहां तक कि उसके अन्दर के मसले थे कि हम और पाकिस्तान मिल कर अपने मामले तय करेंगे वह हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान उसको नहीं मान रहा है ताशकंद घोषणा कोई इस तरह का एग्रीमेंट नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है कि हम पाकिस्तान को कुछ दे दें या उससे कुछ वापस ले लें। उसमें तो यह लिखा हुआ था कि किस प्रकार हम लोग अपने मामलों को तय कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि हमको कुछ ऐसी बात कहने की जरूरत है कि हम उस घोषणा को वापस लेते हैं। जहां तक रूस का सम्बन्ध है, हमने कई मर्तबा सोवियत संघ सरकार को बताया है कि ताशकंद घोषणा में जो बातें थीं, किस तरह से हमने उनके लिए कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान उनको नहीं मानता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हम भी नहीं मानेंगे।

श्री दिनेश सिंह : न मानिये। कौन कहता है कि आप मानिये ?

श्री कंवर लाल गुप्त : स्वयं मन्त्री महोदय ने उस दिन अपने जवाब में कहा था :

> "Pakistan has not agreed to talks on any of the points raised concerning normalisation and improvement of relations under the Tashkent declaration."

यानी पाकिस्तान तो हमारे साथ रिलेशन्ज को नार्मल नहीं करना चाहता है और वह केवल उन्हीं बातों को मानता है, जो उसके हित में हों।

MR. SPEAKER : Let there be no speeches. Let the hon. Member ask a straight question.

श्री कंवर लाल गुप्त : इसके बावजूद यह सरकार पाकिस्तान से बातचीत करती जा रही है। यह ठीक है कि हम किसी भी देश के साथ लड़ाई नहीं चाहते हैं। इस सरकार ने पाकिस्तान को जो नो-वार पैक्ट आफर किया है, वह भी ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान बार-बार कहने के बावजूद इस सरकार की इस बात को नहीं मानता है, तो वह कंट्री की ह्यूमिलिएशन क्यों करती है ? क्या मन्त्री महोदय सदन को यह विश्वास दिलायेंगे कि आईन्दा सरकार पाकिस्तान को नो-वार पैक्ट आफर नहीं करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं समझता कि इस में कोई ह्यूमिलिएशन होता है। माननीय सद-

स्थ जहां खुद देश की ह युमिलिएशन कराते हैं, उसकी बात तो नहीं करते है और दूसरी बातों को लेकर देश में हयुमिलिएशन का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अगर हम किसी देश से कहें कि हम लोग आपस में मिलकर मामलों को सुलझायें और लड़ाई-झगड़ा न करें, तो इसमें हयुमिलिएशन क्या है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : पाकिस्तान तो इस सरकार की बात नहीं मानता हैं। तो क्या सरकार इसी तरह से करती रहेगी ? (**व्यवधान**)

श्री दिनेश सिंह : वह नहीं मानता है, तो क्या हुआ ? (**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब तो आना चाहिए ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जब पाकिस्तान ताशकंद समझौते को नहीं मानता है, तो क्या हम उसको मानते चले जायेंगे ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या इस तरह शाउट करने से वह मान जायेगा ?

MR. SPEAKER : Shri Inder J. Malhotra.

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे सवाल का जवाब दिया जाये।

MR. SPEAKER : Let the hon. Member please sit down.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है ।

MR. SPEAKER : I do not allow further questions.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I do not want to ask any further question, but my earlier question should be replied to.

MR. SPEAKER : The reply to the question has been very clear. If it is not to his liking, that is another matter.

MR. KANWAR LAL GUPTA : It is not clear to anybody. It may be clear only to you.

SHRI INDER J. MALHOTRA : After the signing of the Tashkent Declaration, how many times did the Soviet Prime Minister take any initiative to see that both India and Pakistan agreed on the basic needs and tried to implement the declaration in full ?

SHRI DINESH SINGH : It will be difficult for me to answer on behalf of the Soviet Prime Minister what initiatives he took and how many times he took those initiatives.

SHRI INDER J. MALHOTRA : My question is entirely different. After the singing of the Tashkent Declaration, how many times did the Soviet Prime Minister take the initiative to see that both India and Pakistan tried to implement the declaration in its true spirit ?

SHRI DINESH SINGH : I have already replied to the question and said that I cannot answer on behalf of the Soviet Prime Minister and say how many times he took the initiative and what he did. So far as the discussions with us are concerned, I can give some information to the House. When the Soviet Prime Minister came here, he had talks with us, and when I went to the Soviet Union, we raised this question that we had tried in every possible way to seek a peaceful solution of all of our differences with Pakistan, but Pakistan had not reacted, and they said that they appreciated the steps that we had taken and the efforts that we were making.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जिन परिस्थितियों में ताशकंद समझौता हुआ था, वे भारत के लिये शुभ नहीं थीं । वे इसलिए भी अत्यधिक अशुभ थीं कि भारत को ताशकंद समझौते के समय ही अपने एक प्रधान मंत्री से हाथ धोना पड़ा था । जब कोई तीसरी पार्टी इस तरह का समझौता कराती है, तो उसका यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि यदि किसी एक पक्ष द्वारा उस समझौते का पालन न किया जाये, तो

वह उसके द्वारा उस समझौते का पालन कराने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करे। जैसा कि विदेश मन्त्री ने अभी बताया है, भारत सरकार ने बार-बार रूस सरकार को इस बात से अवगत कराया है कि पाकिस्तान उस समझौते का पालन नहीं कर रहा है। क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में कोई ऐसे तथ्य भी हैं कि रूस ने पाकिस्तान पर यह दबाव डाला कि वह इस समझौते का पालन करे। अगर रूस के दबाव के बावजूद भी पाकिस्तान ने उस समझौते का पालन नहीं किया, तो इस सम्बन्ध में रूस की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूं कि रूस सरकार ने इस मामले पर पाकिस्तान से बातचीत की है और उसने हमारे साथ बातचीत में भी कहा है कि उसने पाकिस्तान के साथ बात की है कि ताशकंद घोषणा के अनुसार दोनों देशों को अपने मामलों को तय करने में आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान ने क्या कहा और रूस सरकार ने क्या कहा, इसका पूरा विवरण तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन उसका जो परिणाम है वह सामने है कि पाकिस्तान अभी इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मेरा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान इस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो रूस की क्या प्रतिक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कन्डप्पन।

SHRI S. KANDAPPAN : It is unfortunate that Pakistan is not able to appreciate the advantages that lie in accepting the Tashkent agreement. But it also seems to me that our Government with their pious hope are passively waiting for a change of mind on the part of the Pakistan Government. Have Government in all these years actively and positively tried to manouvre to see that this is acceptable to Pakistan ?

SHRI DINESH SINGH : I am not quite clear what the manouvre he has in mind is.

SHRI S. KANDAPPAN : Political, diplomatic and otherwise.

SHRI DINESH SINGH : So far as the question of discussion is concerned, we have taken opportunity wherever it was possible to mention to Pakistan that we would wish to settle differences peacefully in accordance with the Tashkent Declaration. Also in this spirit the Prime Minister had made the offer of a no-war pact.

श्री द्वा० ना० तिवारी : हम लोग जानते हैं कि रूस पाकिस्तान को आर्म्ज सप्लाई कर रहा है और वे आर्म्ज हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। क्या मन्त्री महोदय ने कभी रूस से ऐसी बात की है कि वह पाकिस्तान को तब तक के लिए आर्म्ज सप्लाई करना बन्द कर दे, जब तक कि पाकिस्तान ताशकंद समझौते के मुताबिक भारत से बातचीत नहीं करता है और इस प्रकार सब आपसी मामलों को सुलझा नहीं लिया जाता है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां। इस सम्बन्ध में सोवियत संघ सरकार से कई मर्तबा बातें हुई और हमने उनका यहां भी जिक्र किया है। हम ने सोवियत संघ सरकार से कहा कि वह पाकिस्तान को जो आर्म्ज दे रही है, उनसे हमारे लिए खतरा बढ़ता है; जब तक पाकिस्तान और हमारे बीच इस तरह के मामले चल रहे हैं, तब तक पाकिस्तान को हथियार देने से हमारे लिए और खतरा पैदा होता है। इसके बारे में हमने सोविय संघ सरकार से कई मर्तबा बातें की हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : इस बारे में रूस की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ।

SHRI HEM BARUA : Since the offer of a no-war pact with Pakistan was made on the basis of the Tashkent Declaration, since Pakistan has voilated the provisions of the Declaration with impunity and since Mr. Kosygin who is supposed to be the architect of the Tashkent Declaration, puts India on a par with Pakistan in the matter

of violation of this Declaration, are Government prepared to announce to the world that the Tashkent Declaration is dead as dodo, for there cannot be any unilateral implementation of a bilateral pact which the Tashkent Declaration is ?

SHRI DINESH SINGH : I am not clear what particular benefit the hon. member has in making this suggestion, because it is a declaration of intention to settle matters peacefully. Now how can we say that it is dead ? It is a matter that we hope that Pakistan will agree to.

SHRI HEM BARUA : My question is, how can there be a unilateral implementation of a bilateral pact which the Tashkent Declaration is.

SHRI DINESH SINGH : That was the whole point, that it is a declaration, not a pact. The hon. member has read it. He will appreciate that there is no element of giving up in that sense. It is basically a declaration to settle disputes peacefully without going to war.

SHRI HEM BARUA : It is a declaration between two countries, India and Pakistan. India implements it, Pakistan does not.

MR. SPEAKER : No agrument please.

SHRI HEM BARUA : Does the Tashkent Declaration stipulate any obiigation on the part of both the countries which are parties to the declaration to implement it ?

MR. SPEAKER : I request you not to enter into argument when the Minister is replying.

श्री राम सेवक यादव : मंत्री महोदय ने बार-बार बताया है कि सोवियत सरकार ने पाकिस्तान पर ताशकंद समझौते को कार्यरूप में परिणित करने के लिये जोर और दबाव डाला। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कभी सोवियत यूनीयन ने अलग अलग दबाव डालने के अतिरिक्त कभी ऐसा भी करने का प्रयास किया कि दोनों देशों के नेताओं को एकत्रित करे ताकि सब बातें एक दूसरे के सामने आयें और मालूम हो सके कि सचमुच क्या हो रहा है ? दूसरे जब पाकिस्तान ने इस पर कोई तवज्जह नहीं दी तो क्या रूस ने किसी प्रकार से अपनी अनिच्छा या उपेक्षा पाकिस्तान के प्रति दिखाई या नहीं दिखाई ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे चुके हैं।

So many questions have been asked, so much time is taken.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : You used to call one Member from that side, one Member from this side and one from the Centre. Now you are calling only from the Centre. What about us ? (*Interruptions*)

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : In the matter of questions as well as debates, now that the Congress Party is divided, whatever time was being given to the Congress Party should be divided between the two parties.

MR. SPEAKER : I am very much prepared to do like that. (*Interruptions*)

आप रोज क्या खा कर आते हैं, शान्ति से क्यों नहीं चलने देते...(**व्यवधान**) :

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय मैं लगातार बार-बार खड़ा हुआ हूँ।

अध्यक्ष महोदय : बारबार खड़े होने से टाइम नहीं मिलेगा। आप देखिये-आपकी पार्टी ने क्वेश्चन दिया, उन्हें मोका दिया गया, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछे। अभी भी ऐसे बहुत से मेम्बर हैं जिनकी टर्न नहीं आई है जब कि आपकी तरफ से तीन मेम्बर पूछ चुके हैं, फिर भी आप सवाल पूछने के लिये इंन्सिस्ट कर रहे हैं, इस तरह से कैसे काम चलेगा। इस तरह से हम तीन सवालों से ज्यादा आगे नही बढ़ सकेंगे। आपको सोचना चाहिये-कई तरह के इन्टरेस्ट्स होते हैं, कोई रीजनल क्वेश्चन होता है, दूसरे इंटरेस्ट्स होते हैं, अगर इसी तरह से रोटेट करने लगे तो यह लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकेगी।

SHRI P. GOPALAN : The Tashkent Declaration has clearly laid down the necessity of setting up an Indo-Pak joint machinery to discuss what further steps should be taken to normalise Indo-Pakistan relations. I would like to know from the hon. Minister what steps have been taken and how far such steps have been successful and whether there is any proposal with the Goverment to take the initiative to sign a no-war pact with Pakistan along with the setting up of a join machinery to discuss and settle outstanding disputes.

SHRI DINESH SINGH : One meeting between the Ministers of the two countries had taken place shortly after the Declaration was made. Since then it has not been possible to hold another meeting. We are quite ready to go to a meeting or to invite the Pakistanis to come here, but they have not shown any inclination to continue this dialogue.

Regarding the no-war pact, it has been already stated in this House on a number of occasions that Pakistan wanted machinery to be set up and we had said that we would be willing to set up a machinery to discuss all outstanding differences between Pakistan and India.

Export of Tea to U. K.

+

*514. SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI K. HALDER :
SHRI BHAGBAN DAS :
SHRI B. K. MODAK :
SHRI GANESH GHOSH :

Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) the quantity of shipment of tea to U. K. during the first eight months of the years 1968 and 1969 from North and South India, separately ;

(b) whether it is a fact that tea prices have fallen so sharply in U. K that producers in North and South India have cut their shipments for sale in London auction ; and

(c) if so, the Unit value of tea shipped to London during the above period and the steps, if any, being taken to improve the position ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI RAM SEWAK) : (a) to (c). Sir, A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The quantities of tea shipped to the U. K. during the first eight months of 1968 and 1969 from North and South India were :—

	1968	1969
North India	41.06 million kg.	26.94 million kg.
South India	8.46 million kg.	4.32 million kg.

(b) Yes, Sir. Following a steady decline in tea prices realised in the London auctions there has been some diversion of tea to the auctions in India.

(c) The unit values of tea realised in the U. K. during the first eight months of 1968 and 1969 were Rs. 8.40 per kilogram and Rs. 7.38 per kilogram respectively.

With supply in excess of demand in the export market and with the increase in production particularly in the East African Countries reliance is primarily put on international action to stabilise tea price. As an immediate measure, producing countries have agreed to withhold 90 million lbs. of tea from their estimated exports during 1970. An international Consulatative Committee on Tea has been established under the Food and Agriculture Organisation to keep the market situation under constant review and to make recommendations on short-term and medium term measures and later to develop longer-term schemes for stabilising tea prices on equitable and remunerable level.

Producing countries are also considering measures to continue and intensity the campaign for promotion of tea in the U. K.

SHRI JYOTIRMOY BASU : We are facing a real crisis. We are giving 42 per cent of our total export earnings for servicing foreign loans and also as interest, and unless we can really get full value for all the export that we make to foreign countries, we shall be doomed for good. We would like to know from the Government what specific steps they have taken to establish the image of Indian tea as an